

Newspaper Clips

January 11, 2013

Rashtriya Sahara ND 11/01/2013

P-10

फीसवृद्धि पर उठे सवाल

आईआईटी

शशांक द्विवेदी

देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा के खराब हालात और बढ़ती चुनौतियों के बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लमराजू की अध्यक्षता में आयोजित आईआईटी काउंसिल की बैठक में शैक्षिक सत्र 2013 से आईआईटी में ग्रेजुएट स्तर पर दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस में सालाना 50 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपए (80 फीसद वृद्धि) करने का निर्णय लिया गया है। एक तरफ देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 100 वें विज्ञान कांग्रेस में उच्च शिक्षा में बड़े सुधार की वकालत करते हुए उसमें ज्यादा सरकारी निवेश की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार आईआईटी की फीस लगभग दोगुनी कर रही है। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके पहले फीस बढ़ोतरी 2009 में की थी, तब आईआईटी की फीस को 25 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि चार साल में फीस में लगभग चार गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है। जबकि छात्रों-अभिभावकों पर बोझ बढ़ाने वाला यह कदम किसी भी तरह से न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है।

आईआईटी की बढ़ी फीस को लेकर छात्र-अभिभावक सब परेशान हैं। मध्यम व गरीब घरों के बच्चे जो कर्ज लेकर, मां के गहने गिरवी रखकर या एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, वे तो मानसिक तनाव में आ गए हैं कि आखिर कैसे पूरा होगा इंजीनियरिंग का सपना। क्योंकि पहले से तय फीस को लेकर उनके घरों में जो बजट तैयार है वह फीस वृद्धि के फैसले की वजह से अचानक गड़बड़ा सकता है। देश में लाखों गरीब बच्चे-बच्चियां स्कूली जीवन में ही इंजीनियर-डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं लेकिन देश में महंगी तकनीकी शिक्षा की वजह से उनकी इच्छाओं और सपनों पर पानी फिर जाता है। क्या केंद्र सरकार को गरीब प्रतिभावान छात्रों की कोई फिक्र है? किसी देश या समाज के सर्वांगीण विकास में उच्च और तकनीकी शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। गौर से देखा जाए, तो दुनिया के ताकतवर व समृद्ध देशों की सफलता का एक बड़ा कारण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की आर्थिक प्रगति को

उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा से जोड़कर ही समझा जा सकता है। लेकिन हमारे देश के नीति नियंत्रकों को यह बात समझ में नहीं आती। देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वर्तमान सत्र में ही पूरे देश में इंजीनियरिंग की चार लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। इनमें कुछ आईआईटी भी शामिल है जहां 2012 में 300 सीटें और 2011 में 700 सीटें खाली रह गई थीं। उच्च और तकनीकी शिक्षा में निजी और सरकारी सभी संस्थानों में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, जो आम आदमी की पहुंच के बाहर है। इसी वजह से मौजूदा सत्र में पूरे देश में चार लाख से ज्यादा सीटें खाली रह गईं। एक तरफ सरकार भारत को



2020 तक दुनिया की पांच सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रख रही है, राष्ट्रपति महोदय नोबेल पुरस्कार जीतने का आह्वान कर रहे हैं; वहीं दूसरी तरफ देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा का बुनियादी ढांचा ही बेहद कमजोर है। बेरोजगारी और लगातार फीस वृद्धि की वजह से इस क्षेत्र से युवाओं का मोहभंग हो रहा है। दाखिलों का अनुपात साल दर साल कम हो रहा है।

यह हाल तब है जबकि देश की जनसंख्या का मात्र 10 फीसद हिस्सा ही उच्च शिक्षा ले पाता है। इसके विपरीत जापान में 70 फीसद, यूरोप में 50 फीसद व कनाडा और अमेरिका में 80 फीसद लोग उच्च शिक्षा लेते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर साल कोई न कोई कमेटी गठित करती है लेकिन इन कमेटियों की सिफारिशें व्यावहारिक ही नहीं होती। अनिल काकोदकर समिति ने किस आधार पर आईआईटी में लगभग 80 फीसद फीस वृद्धि की सिफारिश की है? इस फीस वृद्धि का

औचित्य क्या है? ये बात देश भी जानना चाहता है। चार साल में फीस में चार गुने की वृद्धि कर सरकार क्या यह दिखाना चाहती है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा सिर्फ साधन संपन्न अमीर लोगों के लिए है? गरीब लोग उच्च शिक्षा के सपने देख ही नहीं सकते। कम से कम गरीब से बुनियादी शिक्षा का अधिकार तो नहीं छिना जाना चाहिए।

सरकार आईआईटी में फीस बढ़ाने के निर्णय को तो इसी सत्र से तुरंत क्रियान्वित कर रही है लेकिन आईआईटी की गुणवत्ता, जवाबदेही व पारदर्शिता के लिए वह गंभीर नहीं है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग बताने वाली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ताजा सूची में आईआईटी सहित भारत के किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय को दुनिया के शीर्ष दो सौ संस्थानों में भी जगह नहीं मिली है। देश में अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात आईआईटी की भी साख विश्व स्तर पर धूमिल होती जा रही है। विश्व के सात सौ संस्थानों पर किए गए इस सर्वे में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग लगातार नीचे ही गिर रही है। आईआईटी-दिल्ली 202 से गिरकर अब 218वें स्थान पर है और आईआईटी-मुंबई 187 से 225 वें स्थान पर। इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले अमेरिकी मैसाच्युसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी (एमआईटी) से आईआईटी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। दोनों में शिक्षा, शोध और फैकल्टी के मामले में जमीन-आसमान का अंतर है। इसका प्रमाण तो यही है कि एमआईटी की फैकल्टी में 77 नोबेल पुरस्कार विजेता संबद्ध हैं। देश में अनुसंधान की स्थिति, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीयकरण के पैमाने पर भी आईआईटी कमतर ही साबित हुए हैं। यह चिंतनीय विषय है कि हमारे आईआईटी इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं जाता।

दुर्भाग्य से अभी देश में तकनीकी शिक्षा का जो स्तर है वह ठीक नहीं है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मौजूदा नीतियों के आधार पर उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार असंभव है। शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी हक है, इसे निशुल्क या बहुत कम फीस पर छात्रों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आईआईटी में फीस बढ़ोतरी से कमजोर वर्गों के उन छात्रों के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, जिनमें प्रतिभा है और वे आईआईटी से पढ़कर आगे जाना चाहते हैं। इससे सामान्य छात्र भी प्रभावित होंगे। क्या हम अपने बच्चों, देश की आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी स्थिति विकसित नहीं कर सकते कि फीस आदि को लेकर उनमें अवसाद या तनाव न पैदा होने पाए।

Business Standard ND

11/01/2013 11

Look beyond govt funding

IITs can't expect the Centre to finance them forever

The decision by the Indian Institutes of Technology (IITs) to increase tuition fees by 80 per cent – from ₹50,000 to ₹90,000 per annum – is a welcome step in correcting the fee distortions prevalent in most state-owned higher education institutions. The last such fee increase was in 2008 (a 50 per cent hike) and even the worst critics of such fee hikes would admit that another revision was long overdue. In fact, Tuesday's decision should hopefully be the starting block for removing the disparities with private engineering institutes, many of whom have been charging nearly 200 per cent more than what IITs do. The point is even after the latest revision, the IITs' income from fees will be woefully short of the ₹2.5 lakh they spend per student per year and would do little to provide any financial cushion in terms of meeting their operating expenses. Given the inflation, campus costs have been going up by 10 per cent every year; the IITs argue they cannot expect the existing fees to take care of their expenses — capital plus operating costs. No one can fault this logic.

A key recommendation of the Kakodkar Committee last year was that the IITs become financially independent of non-Plan (operational) budgetary support to meet their operating expenditure, while their capital and infrastructure expenditure continue to be met fully under the government's capital budget support plan. (The IITs are now 80 per cent funded by the government.) The Kakodkar Committee had in fact recommended the fee for undergraduate, Masters and PhD programmes to be ₹2-2.5 lakh per annum. If accepted, this could have freed up government resources to be used in primary and secondary education, areas in which the state needs to invest a lot more to create basic infrastructure and capacities.

The logic of these recommendations, however, failed to persuade the IIT directors and the empowered task force that had been set up to examine the Kakodkar report. They argued that the IITs had seen many students from financially modest backgrounds and these bright and deserving candidates would find it impossible to bear the burden of a steep increase in fees. This argument, however, ignores successful global models in which education loans help those who can't pay. Also, experts have claimed that full acceptance of the recommendations will have to wait since the National Academic Depository Bill is yet to be cleared by Parliament. The Bill would enable a shift to "demat" degrees. Then, the degrees of IIT graduates would reflect an obligation to repay the institution and money would come through the employer. The Bill also suggests using the Aadhaar-based system to fund needy students, who, after completing their degree, can be tracked across the country to recover the loan. Once Aadhaar is fully rolled out, the argument suggests that the needs of the underprivileged admission seekers to the IITs or IIMs can be much more easily addressed and the IITs can be bolder in their fee hikes. Having said that, it's also a fact that fee increases alone aren't enough. Instead of depending on the government, the IITs will have to look at generating funds from other sources just as their counterparts in the United States do — tapping alumni and industrial research, for example.

Dainik Jagran Kanpur 10.01.2013 P-2

आईआईटी व यूनीलिवर चलेंगे साथ-साथ

कानपुर, नगर प्रतिनिधि : शोध को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी एवं कंज्यूमर गुड्स कंपनी यूनीलिवर अब साथ-साथ चलेंगे। इंडस्ट्री के साथ कदमताल करने की दिशा में मंगलवार को एमओयू साइन हुआ। खास बात यह रहेगी की शोध में पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहेगा।

आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर इंद्रानिल

मन्ना ने कहा कि शोध को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री और सरकार द्वारा अनुदानित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ काम करने के लिए संस्थान इच्छुक है। इस समझौते से काकोदकर समिति की संस्तुतियों का भी सम्मान होगा। समाज में पहचान भी बनेगी। शोध के प्रोजेक्ट पर कंपनी के साथ मिलकर



काम किया जाएगा। बंगलुरु से आए कंपनी के उपाध्यक्ष डॉ. विलास सिनकार ने कहा कि इस गठबंधन का नतीजा कंज्यूमर गुड्स में दिखेगा। शोध से कंपनी का व्यापार फले-फूलेगा। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर कंपनी 190 देशों में

◆ शोध के क्षेत्र में इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन

फूड, होम एवं पर्सनल केयर के उत्पाद के बूते उपभोक्ताओं तक पहुंच बना चुकी है। आईआईटी की पदार्थ एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ कंपनी को मिलेगा, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी एशिया का पहला संस्थान है जिससे यूनीलिवर ने हाथ मिलाया है।

Asian Age ND 11/01/2013

P16

ISSUES

Scientific discoveries may help humans live forever



Arindam Chaudhuri
MY SPACE

I got to think of three key things that I want to share. The first being about the goodness of doctors. Yes, I still believe doctors have fallen down to almost being the merchants of death (refer to my past editorial at www.thesundayindian.com/en/story/r-un-the-merchants-of-death

are-anxious/36061/). But at the same time, the fact is that we also have a set of amazing human beings, who choose this profession selflessly to make a difference to others' lives.

The second thing that I feel strongly was about the greatness of medical science. Yes, I did argue about the excesses of patents but thanks to their R&D, we live in a better world, where hope never dies.

The desirability of living forever and how that is the ultimate goal of medical science. This is the third issue that I want to leave my readers with today!

Ray Kurzweil — dubbed the smartest futurist in the world by Bill Gates — says that those of us who live

for another 20 odd years might actually go on to live forever or very, very long.

According to him, in another 20 years, science would probably invent ways to reprogramme our bodies and thereby reverse the ageing process; and then, nanotechnology — for instance, nanobots that can be used to destroy tumours, unblock clots, perform operations without scars, replacing blood cells in human bodies — will let us live forever.

My initial reaction was not as futuristic as the prediction. I don't want to live forever, is what I thought. Why should I? Today, I run behind my work, love people close to me that little extra, come back home

early to spend time with my parents, all because of the fear that time is running out.

Will I behave the same when such a fear doesn't exist anymore? Wouldn't I be horribly bored anyway? And of course, if people are run through nanobots, how would we differ from robots? And would you really wish to stay with the same spouse for so many years, or love your great, great, great, grandson as much as you do your grandson now?

While my brother-in-law and friend Prashanto has always been vehemently for the idea of living forever. He believes we have so much to see. I have always thought that life's, happi-

ness was about spending more meaningful time with people you love.

However, one such day, while this debate was going on fiercely at my home, my son, who was 9 years old then and listening all along, almost broke down. He said, "Papa, why won't you take the medicine that could help you live forever? What makes you think that we shall become inhuman robots? We shall be different. We shall remain as loving and caring."

I remember that for many days after that, the only thing bothering my son was the fear that I may not be willing to live forever. Thus, at this point of time, seeing in my son's

eyes the love for all of us every day, seeing in Prashanto's eyes the love for his mother, I am forced to think that the idea of living forever may not be that bad after all.

If we laud every medical advancement that helps us live a little longer, shouldn't living forever be considered the ultimate discovery? Most importantly, whom do we live for? If you were to ask me, we live for others. And if my son, who loves me the most, thinks I must live with him forever, then I want to live with him forever. And wait for life to show how to live.

(The author is a management guru and honary director of IIPM Think tank)

Times of India ND 11/01/2013 P17

Insulin code out, say bye to needles

Breakthrough May Soon Enable Diabetics To Get Rid Of Daily Injections

Melbourne: In a major breakthrough that could help millions of diabetics, Australian researchers have solved a 20-year mystery that could spell the end of daily injections. The new knowledge on how insulin works at a molecular level could be exploited to develop improved insulin medications to treat both type 1 and type 2 diabetes, they said.

Researchers from the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research have captured the first three-dimensional images of insulin "docking" to its receptor, a mystery scientists have been



NO PRICK, NO PAIN

trying to solve for two decades. Previously, scientists remained unsure as to how insulin binds to the receptor on the surface of cells to allow them to take up sugar from the blood and transform it into energy.

The international research team was led by scientists from the Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) in Melbourne, with collaborators from La Trobe University, the University of Melbourne, Case Western Reserve University, the University of Chicago, the University of York and the Institute of Organic Chemistry

and Biochemistry in Prague.

Lead researcher Mike Lawrence, an Associate Professor at the institute's Structural Biology division said, "This discovery could conceivably lead to new types of insulin that could be given in ways other than injection, or an insulin that has improved properties or longer activity so that it doesn't need to be taken as often.

"It may also have ramifications for diabetes treatment in developing nations, by creating insulin that is more stable and less likely to degrade when not kept cold, an angle being pursued by our

collaborators. Our findings are a new platform for developing these kinds of medications," Lawrence said.

The insulin is a key treatment for diabetics, but there are many ways that its properties could potentially be improved, the Gizmag website reported. "Understanding how insulin interacts with the insulin receptor is fundamental to the development of novel insulins for the treatment of diabetes.

"We can now exploit this knowledge to design new insulin medications with improved properties, which is very exciting," he said. PH

Volunteers to Mars: Resilient, resourceful persons required

Srinivas Laxman | TNN

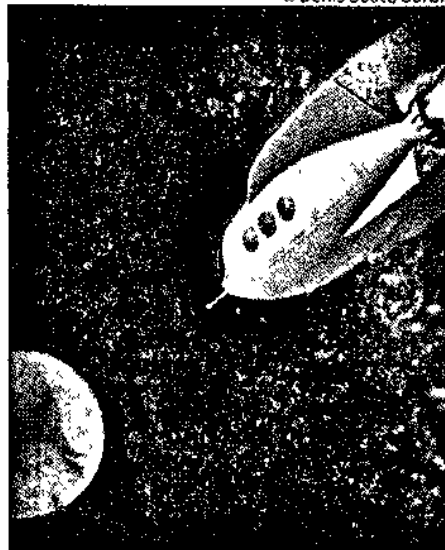
Mumbai: On January 8, 2013, a major step towards launching a manned mission to Mars was initiated. Interestingly, the exercise was neither by Nasa nor the European Space Agency nor the Japanese Aerospace Exploration Agency, but a private Dutch organization called Mars One which plans to establish a human settlement on the Red Planet in 2023.

On Tuesday, it announced requirements for the Mars astronaut selection programme, marking the first step towards a global selection process which will kick off in the first half of this year.

The criteria laid down by Mars One stipulates that the “applicants need to be at least 18 years of age, have a deep sense of purpose, willing to build and maintain healthy relationship, the capacity for self reflection and ability to trust. They must be resilient, adaptable, curious, creative and resourceful”.

Suzanne Flinkenfolgel, director of communication of Mars One has stated that even prior to Tuesday’s announcement, the organisation received more than 1000 emails from individuals who desire to go to Mars.

The announcement says that “it is not necessary to have military training, or experience in flying aircraft nor even a science degree. It is most important that each applicant be intelligent, in good mental and physical health and be willing to dedicate eight years to training and learning before mak-



© Denis Scott/Corbis

DREAM VOYAGE

ing the journey..”

Mars One will maintain 40 trained astronauts during the first duration of the mission.

The plan envisages launching a supply mission in 2016 landing on the Red Planet in October 2016. It will carry 2500kg of cargo comprising spare parts, solar photovoltaic panels and general supplies.

Thereafter, in September 2022, the first four astronauts will be launched to Mars landing in 2023 after a seven to eight month flight. There is no return trip.

For this mission, Mars One plans to use US’s Space X Falcon heavy rocket. It also anticipates the use of a variant of the Space X Dragon capsule, first tested in 2010, which successfully docked with the International Space Station in May 2012. The Dragon will carry the astronauts to Mars.

Bright star Vega may have its planet family

Astronomers have discovered that Vega — the second brightest star in the northern night sky — may have a family of planets similar to our Sun’s. Astronomers have discovered evidence of an asteroid belt surrounding the star like the one that circles the Sun which suggests Vega is likely to have a solar system containing rocky planets similar to Earth or Mars. In our own system, the asteroid belt beyond the orbit of Mars is maintained by the gravity of rocky planets and gas giants such as Jupiter and Saturn. Scientists believe Vega has an inner asteroid belt and outer belt of debris separated by a gap. PTI

‘Spacetime more like whisky than beer’

Space-time continuum may be less like a frothy quantum beer and more like a sipping Einsteinian whiskey, a scientist has claimed. Astrophysicist Robert Nemiroff of Michigan Technological University and Nasa Goddard, reached this conclusion after studying the tracings of three photons of varied wavelengths that were recorded by Nasa’s Fermi Gamma-ray Space Telescope in May 2009, the Science Daily reported. The photons originated about 7 billion light years away from Earth in one of three pulses from a gamma-ray burst. PTI

HT New Delhi

Dr. M. M. Pallam Raju unveils NBT and MHRD calendar 2013

Dr. M. M. Pallam Raju, Minister for Human Resource Development unveiled the MHRD desk calendar, NBT planner and NBT wall-calendar



at a release function held at Shastri Bhawan, New Delhi.

While releasing the calendars, Dr Raju said that a lot of thought has been applied for selecting the theme and designing of the calendars. On the occasion, A. Sethumadha-

van, Chairman, NBT said that the trust has constituted an advisory panel constituting scholars and writers from different parts of the country. The panel is working for bringing out the books based on the teachings of Swami Vivekananda.